बंगलूरू भगदड़ः राज्य सरकार 25 लाख रु. की सहायता देगी

बंगलूरू, 07 जून। बंगलूरू भगदड़ मामले में कर्नाटक सरकार ने शनिवार शाम को मुआवजे की राशि को बढ़ाने का एलान किया है। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने मृतकों के परिवारों को 25 लाख रुपया मुआवजे के रूप में देने की घोषणा की है। पहले यह रकम

- **कर्नाटक सरकार ने पहले मृतकों के परिजनों को दस-दस लाख रु. की सहायता देने की घोषणा की थी, जिसे अब बढ़ा दिया गया है। आरसीबी भी मृतकों के परिजनों को दस-दस लाख रु. की सहायता देगा।**

10 लाख थी। वहीं, आरसीबी भी इस हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए 10-10 लाख रुपए के मुआवजे का एलान कर चुकी है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने चिन्नास्वामी स्टेडियम हादसे में मृतकों के परिजनों को मुआवजा राशि बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने का आदेश दिया।

कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी को "एस.यू.वी." बताया

एस.यू.वी. से कांग्रेस का तात्पर्य है, "स्वयं उद्घोषित विश्वगुरू"

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

- **कांग्रेस के प्रवक्ता, जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा कि भारत के बारे में जो दावा देशी व सरकारी मीडिया कर रहा है और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्य देशों का "परसैप्शन" है, उसमें भारी अन्तर है।**
- **जयराम रमेश ने लिखा है कि नीति आयोग में प्र.मंत्री अपना भाषण दे रहे थे। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अफसर ने बड़े नाटकीय ढंग से घोषणा की कि भारत विश्व में तीसरे नम्बर पर आ गया है, इकॉनमी की दृष्टि से जापान को पीछे छोड़ते हुए।**
- **दूसरी और आईएमएफ ने अपने आंकड़ों के आधार पर घोषणा की कि भारत चौथे नम्बर पर है तथा अगले दो-तीन साल में, ज़र्मनी को पीछे छोड़ते हुए तीसरे नम्बर पर आ जायेगा।**
- **कई अप्रवासी भारतीयों ने, जैसे, हॉटमेल के सबीर भाटिया ने कहा कि चौथे नम्बर पर आने पर सभी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, पर, समृद्धि सड़कों पर तो नज़र नहीं आती। आर्थिक विषमता की दृष्टि से जरूर सबसे अव्वल हो सकता है, समृद्धि की दृष्टि से नहीं।**

नई दिल्ली, 7 जून। भारत की वैश्विक आर्थिक रैंकिंग को लेकर केंद्र सरकार के परस्पर विरोधाभासी बयानों पर तंज कसते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को देश का पहला एस.यू.वी. 'स्वयं उद्घोषित विश्वगुरु' करार दिया।

जयराम रमेश ने सोशल मीडिया मंच एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट में देश के इकोनॉमिक स्टेचर (आर्थिक कद) को लेकर घरेलू दावों और अंतराष्ट्रीय आकलनों के बीच अंतर को उजागर किया।

उन्होंने लिखा, "24 मई 2025 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए नीति आयोग के सीईओ ने यह नाटकीय घोषणा की कि भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है।"

रमेश ने इस दावे के विपरीत कैनडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के हालिया बयान का हवाला दिया। उन्होंने कहा, "अब कैनडा के पूर्व केन्द्रीय बैंकर, एक प्रतिष्ठित पेशेवर अर्थशास्त्री हैं और कैनडा तथा इंग्लैंड के केन्द्रीय बैंक के गवर्नर रह चुके हैं, कहते हैं कि भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।"

प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए जयराम रमेश ने कहा, "शायद भारत के पहले एस.यू.वी.- 'स्वयं उद्घोषित विश्वगुरु' - कुछ ही दिनों में कैनडा के अपने समकक्ष को अपडेट कर सकें।"

कांग्रेस सांसद की टिप्पणियों ने, सरकार के तेज आर्थिक प्रगति के कथानक को चुनौती दी है, और इन अधिकारिक दावों के समय और सटीकता पर सवाल उठाए हैं। उनके द्वारा एस.यू.वी. शब्दों का प्रयोग विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री की आत्मप्रशंसा वाली भाषा की एक तीखी आलोचना है।

ये टिप्पणियाँ ऐसे समय पर आई हैं जब भारत की वैश्विक आर्थिक स्थिति को लेकर विभिन्न संस्थाओं द्वारा अलग-अलग आंकड़े दिए जा रहे हैं और इस विषय पर लगातार बहस जारी है।

आई.एम.एफ. के डेटा के अनुसार, जापान से आगे निकलकर भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। नीति आयोग के सीईओ बी.वी.आर. सुब्रमण्यम ने 10वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। हम 4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था हैं और यह मेरा आंकडा नहीं है, यह आई.एम.एफ. का डेटा है। आज भारत जापान से बड़ा है।" उन्होंने यह भी कहा कि अगले ढाई से तीन वर्षों में भारत जर्मनी को भी पीछे छोड़ तीसरे स्थान पर पहुंच सकता है।

सुब्रमण्यम ने अनुमान लगाया है कि भारत अगले ढाई से तीन वर्षों में जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरे स्थान पर पहुँच जाएगा।

हालांकि इस उपलब्धि की उद्योग जगत और सरकारी अधिकारियों ने सराहना की है, लेकिन सोशल मीडिया पर उद्योग ने इसे आलोचना और शंका की दृष्टि से देखा है - खासकर उन लोगों ने जो आम लोगों के जीवन में इसके असर को लेकर चिंतित हैं। भारत की जी.डी.पी. का आँकड़ा प्रभावशाली होने के बावजूद, प्रति व्यक्ति जी.डी.पी. के मामले में भारत 144वें स्थान पर है। यह देश में भारी आय विषमता और कई छोटे देशों की तुलना में निम्न औसत जीवन स्तर को दर्शाता है।

हॉटमेल के सह-संस्थापक सबीर भाटिया ने इस घोषणा के इर्द-गिर्द छाए जश्न के माहौल की तीखी आलोचना की।

उन्होंने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर इस घोषणा को लेकर तीखी आलोचनात्मक भाषा में लिखाः "हर कोई भारत के चौथे सबसे बड़े अर्थव्यवस्था बनने पर इतरा रहा है। लेकिन सड़कों पर समृद्धि कहाँ है? इतने लोग देश छोड़ने को क्यों व्याकुल हैं?"

भाटिया ने आगे लिखाः "अगर लोग प्रगति को महसूस नहीं कर पा रहे, तो जी.डी.पी. रैंकिंग का क्या मतलब? उन्होंने आर्थिक विकास के वास्तविक प्रभाव पर सवाल उठाया।

उनकी टिप्पणियों की गूंज कई सोशल मीडिया यूज़र्स की प्रतिक्रियाओं में भी सुनाई दी, जिन्होंने भारत की नई आर्थिक स्थिति के बावजूद, देश में अभी भी बनी हुई प्रणालीगत समस्याओं पर निराशा जताई।

एक यूज़र ने लिखाः "चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था - ठीक है। लेकिन जश्न मनाने के लिए बहुत कम है।" "अभूतपूर्व संपत्ति असमानता, चिंताजनक प्रति व्यक्ति आय, भ्रष्टाचार, शर्मनाक बुनियादी ढांचा, टैक्स टेररिज़्म, और 'ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस' मज़ाक बन चुका है। चिंता करने के लिए बहुत कुछ है।" एक अन्य यूज़र ने यह भी इंगित किया कि भारत की प्रति व्यक्ति आय अभी भी कई छोटे देशों से काफी कम है।

पोस्ट में आगे कहा गया, "हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, फिर भी, 2,878 डॉलर (लगभग 2,44,000 रु.) के साथ, प्रति व्यक्ति आय के मामले में 144 वें स्थान पर हैं। हम श्रीलंका, भूटान, और विशेष रूप से त्रिनिदाद और टोबैगो जैसे देशों से भी पीछे हैं, जहाँ प्रति व्यक्ति आय 18,445 डॉलर (15 लाख रु से अधिक) है।"

चीन पाकिस्तान को अत्याधुनिक विमान व मिसाइल डिफेंस सिस्टम देगा

बीजिंग/इस्लामाबाद, 07 जून। चीन और पाकिस्तान के बीच सैन्य संबंधों को और मजबूत करते हुए, बीजिंग ने इस्लामाबाद को अपने उन्नत जे-35 स्टील्थ विमानों के साथ-साथ अपने केजे-500 एडब्ल्यूएसीएस और एचक्यू-19 मिसाइल रक्षा प्रणालियों की पेशकश की है। संघीय सरकार द्वारा अपने आधिकारिक एक्स/ट्विटर अकाउंट पर साझा की गई जानकारी के अनुसार, चीनी सरकार ने 40 जे-35 स्टील्थ विमान, केजे-500 एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल (एडब्ल्यूएसीएस) सिस्टम और एचक्यू-19 मिसाइल रक्षा प्रणाली की आपूर्ति का प्रस्ताव दिया है, जिससे दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। समा टीवी की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गयी। चीन के शेनयांग एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन (एसएसी) द्वारा निर्मित यह चेंगदू जे-20 विमान के बाद चीन में दूसरा 5वीं पीढ़ी का विमान है। चीनी मीडिया के अनुसार, विमान उन्नत सेंसर, बहु-भूमिका क्षमता आधारित एवियोनिक विशेषताओं, सटीक निर्देशित मिसाइल प्रणालियों, एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों से सुसज्जित है जिन्हें विशेष रूप से ईएमपी हथियारों से जामिंग को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

'मैं कोई चोर या भगोड़ा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

- **कांग्रेस व विपक्ष को मोदी सरकार को घेरने के लिए एक और मुद्दा मिल गया है, माल्या के "रहस्योद्घाटन" से। विपक्ष का आरोप है, कई बड़े-बड़े व्यापारी, जैसे, माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, आदि, बैंकों का हजारों करोड़ रूपये डकार कर विदेश जाकर बैठ गये हैं तथा केन्द्रीय सरकार अब कुछ नहीं कर पा रही है।**

मनी लॉन्ड्रिंग शामिल हैं। ये मामले उनकी एयरलाइंस के पतन और भारतीय बैंकों से लिए गए 9,000 करोड़ से अधिक के डिफॉल्टेड लोन से जुड़े हैं। लंदन में मीडिया को दिए एक हालिया बयान में माल्या ने दावा किया कि 2 मार्च 2016 को भारत छोड़ने से पहले उन्होंने अरुण जेटली से मुलाकात की थी ताकि बैंकों के समूह के साथ सेटलमेंट पर बात हो सके, और उन्होंने अपनी यात्रा की जानकारी भी दी थी।

माल्या ने कहा, "भारत से भागा नहीं। मैंने खुलेआम और वैध पासपोर्ट के साथ देश छोड़ा था, सरकार को सूचित करने के बाद।" उन्होंने यह भी कहा कि उनका प्रस्थान गोपनीय नहीं था और वह उस समय सरकारी अधिकारियों के संपर्क में थे। उन्होंने खासतौर पर यह कहा कि उन्होंने रवाना होने से एक दिन पहले संसद में जेटली से मुलाकात की थी और वित्तीय सैटलमैंट की इच्छा जताई थी।

रिपोर्ट्स के अनुसार, उस समय मोदी सरकार में एक प्रभावशाली मंत्री रहे अरुण जेटली ने कथित तौर पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था, यह कहते हुए कि मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई माल्या के प्रस्थान के 48 घंटे बाद, यानी 3 मार्च 2016 को तय थी। इसके बावजूद माल्या भारत से जिनेवा होते हुए लंदन चले गए, जहां वह अब तक रह रहे हैं, हालांकि, भारत सरकार ने उन्हें प्रत्यर्पित कराने की कई कोशिशें की हैं।

कांग्रेस पार्टी ने इस मौके को भुनाते हुए मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने यह सवाल उठाया कि जब माल्या पर भारतीय बैंकों को धोखा देने का आरोप था, तब वह सरकार की जानकारी के बिना देश से बाहर कैसे जा सकते थे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक प्रेस वार्ता में कहा, "यह एक और उदाहरण है कि मोदी सरकार अपने पूंजीपति दोस्तों को कैसे बचाती है। विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, सभी को देश से भागने दिया गया।" आर्थिक और कानूनी विशेषज्ञों ने भी माल्या के ताज़ा दावों पर सवाल उठाए हैं। कुछ ने इस बात की ओर इशारा किया है कि 2014 में भाजपा के सत्ता में आने के बाद माल्या की सत्ताधारी नेताओं से नज़दीकी ने संभवतया सरकार की कार्यवाही को प्रभावित किया हो। एक वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक ने कहा, "यह तथ्य कि माल्या सीधे वित्त मंत्री से मिल सकते थे और हस्तक्षेप की मांग कर सकते थे, असामान्य है और इसके उनकी पहुंच और विशेषाधिकार पर सवाल उठाते हैं।"

इस नए खुलासे के साथ ही भगोड़े आर्थिक अपराधियों को लेकर चल रही बहस फिर से सियासी चर्चाओं में प्रमुखता से लौट आई है। जैसे-जैसे सुप्रीम कोर्ट माल्या से जुड़े विभिन्न मामलों की सुनवाई करता रहेगा, उनके सार्वजनिक बयानों ने न केवल जनता की यादें ताज़ा कर दी हैं, बल्कि मोदी सरकार को हाई-प्रोफाइल घोटालों से निपटने के अपने तरीके को लेकर रक्षात्मक मुद्रा में ला दिया है।

थरुर भाजपा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सरकार के नेतृत्व में इस पहल में भागीदारी और आतंकवाद से निपटने को लेकर मोदी सरकार की खुलकर प्रशंसा करने को कांग्रेस के कुछ नेताओं ने इसे पार्टी लाइन से अलग रुख माना है। इसको लेकर कांग्रेस में उनके भविष्य को लेकर चर्चाएं भी तेज हो गई हैं।

हालांकि इन घटनाक्रमों के बावजूद, थरूर ने सार्वजनिक रूप से भारत की उदार और बहुलवादी विचारधारा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है और वैचारिक मतभेदों के कारण भाजपा में शामिल होने की संभावना को खारिज किया है।

संक्षेप में कहें तो शशि थरूर की हालिया गतिविधियों से यह संकेत जरूर मिलता है कि वे राष्ट्रीय मुद्दों पर सरकार के साथ सहयोग के इच्छुक हैं, लेकिन फिलहाल मोदी सरकार या भाजपा में उनके शामिल होने का कोई ठोस संकेत नहीं है।

शुक्रवार को उनके नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से मुलाकात की, जबकि उसी दिन कांग्रेस ने दावा किया था कि यह प्रतिनिधिमंडल किसी भी प्रभावशाली नेता से मिले बिना लौट रहा है। इस मुलाकात ने कांग्रेस के दावे को भी खारिज कर दिया।

चुनाव आयोग ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अपने जवाब में ये सभी तथ्य सामने रखे थे, जो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। ऐसा लगता है कि बार-बार ऐसे मुद्दे उठाते हुए इन सभी तथ्यों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है।

चुनाव आयोग ने यह भी लिखा कि किसी के द्वारा प्रसारित कोई भी गलत सूचना चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त हजारों प्रतिनिधियों की बदनामी तथा चुनाव कर्मचारियों का मनोबल तोड़ने वाला होता है, जो इस बड़ी कवायद के लिए अथक परिश्रम करते हैं। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र की मतदाता सूची को लेकर लगाए गए निराधार आरोप कानून के शासन का अनादर है।

नई राजनीतिक...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

हो। आश्चर्यजनक रूप से, 80 प्रतिशत से अधिक लोग पोल से सहमत थे।

उन्होंने शुक्रवार शाम को लिखा जनता ने अपनी बात कह दी है। मध्य वर्ग के 80 प्रतिशत लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए अमेरिका में एक नई राजनीतिक पार्टी की जरूरत है ! और ठीक 80 प्रतिशत लोग इससे सहमत हैं। यही नियति है।

इसके बाद मस्क ने एक प्रशंसक के इस सुझाव का समर्थन किया कि वे इसे "अमेरिका पार्टी" नाम दें।

सोनिया गांधी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के प्रमुख मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने पुष्टि की कि वे महज़ एहितयात के तौर पर अस्पताल गई थीं और सोनिया गांधी की स्थिति स्थिर है तथा वे निगरानी में हैं।

एसओजी ने पुलिस अकादमी से ट्रेनी एसआई को गिरफ्तार किया

गिरफ्तार किये गये विजेन्द्र कुमार जोशी की आरपीए की इंटैलिजैंस ट्रेनिंग अकादमी में ट्रेनिंग चल रही थी

- **कोर्ट ने आरोपित ट्रेनी एसआई को दो दिन की रिमांड पर एसओजी को सौंपा है। कहा जा रहा है कि दो दिन की पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं।**

जयपुर, 7 जून। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने सब इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती पेपर लीक मामले में कार्रवाई करते हुए राजस्थान पुलिस अकादमी (आरपीए) की इंटेलिजेंस ट्रेनिंग अकादमी से ट्रेनी एसआई को गिरफ्तार किया है। अब तक की जांच में सामने आया कि एसआई भर्ती परीक्षा से पहले पेपर पढ़कर पास होने में नाम सामने आने पर यह कार्रवाई की। जहां एसओजी की टीम ने शनिवार दोपहर आरोपित ट्रेनी एसआई को कोर्ट में पेश किया, जहां पूछताछ के लिए कोर्ट ने उसे दो दिन के रिमांड पर एसओजी को सौंपा है। एसओजी के दो दिन की पूछताछ में कई चौकाने वाले खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है।

एडीजी (एसओजी) वीके सिंह ने बताया कि एसओजी की टीम ने सब इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती पेपर लीक मामले में कार्रवाई करते हुए ट्रेनी एसआई विजेन्द्र कुमार जोशी (30) निवासी बलारा जिला सीकर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार ट्रेनी एसआई विजेन्द्र कुमार जोशी की राजस्थान पुलिस अकादमी (आरपीए) जयपुर स्थित इंटेलिजेंस ट्रेनिंग अकादमी में ट्रेनिंग चल रही थी।

एसओजी ने गुरुवार को कार्रवाई कर एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में आरोपित पुरुषोत्तम दाधीच (35), संदीप कुमार लाटा (42) और कुंदन कुमार पण्ड्या (54) को गिरफ्तार किया था। तीनों आरोपितों से पूछताछ में ट्रेनी एसआई विजेन्द्र कुमार जोशी का नाम सामने आया था कि एसआई भर्ती परीक्षा से पहले आरोपित विजेन्द्र कुमार जोशी ने पेपर पढ़ा था।

पूछताछ के आधार पर आगे कार्रवाई करते हुए एसओजी ने ट्रेनी एसआई विजेन्द्र कुमार जोशी को गिरफ्तार किया।

पूर्व में गिरफ्तार एसआई रेनू, सुरेन्द्र बगड़िया और सुरजीत ने भी परीक्षा से पहले पेपर पढ़ा था। इनको पेपर पढ़ाने में आरोपित पुरुषोत्तम दाधीच, संदीप कुमार लाटा और कुंदन कुमार पाण्ड्या की ही भूमिका रही है।

'मेरी हालत गंभीर है मैं रहूँ या ना रहूँ, पर देशवासियों को सच्चाई बताना चाहता हूँ'

जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कथित भ्रष्टाचार केस में जनता के सामने अपना पक्ष रखते हुए भावुक पोस्ट लिखी

- **मलिक ने लिखा, जिस प्रोजैक्ट की मंजूरी के लिए मुझे डेढ़ सौ करोड़ रु. की रिश्वत की पेशकश की गई उसे मैंने उसे कैंसल कर दिया था, अब उसी में मुझ पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं।**
- **मलिक इन दिनों गंभीर रुप से बीमार हैं और आईसीयू में एडमिट हैं। उन्होंने वहीं से पोस्ट लिखी। मलिक ने लिखा, अगर मेरे पास पैसा होता तो प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराता।**

नई दिल्ली, 07 जून। जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक इन दिनों अस्पताल में भर्ती हैं। इससे पहले सीबीआई ने सत्यपाल मलिक और 6 अन्य लोगों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। उनके खिलाफ कीरु हाइड्रो प्रोजेक्ट से जुड़े कथित करप्शन केस में मामला दर्ज किया गया था। सत्यपाल मलिक ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर एक भावुक पोस्ट की है। सत्यपाल मलिक ने एक्स पर लिखा, "नमस्कार साथियों। मैं पिछले लगभग एक महीने के अस्पताल में भर्ती हूं और किडनी की समस्या से जूझ रहा हूं। आज फिर से मुझे आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा। मेरी हालत बहुत गंभीर होती जा रही है। मैं रहूं या ना रहूं इसलिए अपने देशवासियों को सच्चाई बताना चाहता हूं।"

उन्होंने आगे लिखा, "जब गवर्नर के पद पर था तो उस समय मुझे 150-150 करोड़ रूपए की रिश्वत की पेशकश भी हुई, परंतु मैं मेरे राजनीतिक गुरु किसान मसीहा स्वर्गीय चौधरी चरणसिंह जी की तरह ईमानदारी से काम करता रहा और मेरा ईमान वो कभी डिगा नहीं सकें। जब मैं गवर्नर था उस समय किसान आंदोलन भी चल रहा था, मैंने बगैर राजनीतिक लोभ लालच के पद पर रहते हुए किसानों की मांग को उठाया। फिर महिला पहलवानों के आंदोलन में जंतर-मंतर से लेकर इंडिया गेट तक उनकी हर लड़ाई में उनके साथ रहा।"

सत्यपाल मलिक ने लिखा, "पुलवामा हमले में शहीद वीर जवानों के मामले को उठाया, जिसकी आज तक इस सरकार ने कोई जांच नहीं करवाई है। सरकार मुझे सीबीआई का डर दिखाकर झूठे चार्जशीट में फंसाने के बहाने ढ़ूंढ रही है। जिस मामले में मुझे फंसाना चाहते हैं उस टेंडर को मैंने खुद निरस्त किया था, मैंने खुद प्रधानमंत्री जी को बताया था इस मामले में करप्शन है और उन्हें बताने के बाद में मैंने खुद उस टेंडर को कैंसिल किया, मेरा तबादला होने के बाद में किसी अन्य के हस्ताक्षर से यह टेंडर मंजुर हुआ।"

उन्होंने लिखा, "मैं सरकार को और सरकारी एजेंसियों को बताना चाहता हूं कि मैं किसान कौम से हूं, मैं ना तो डरने वाला हूं ओर ना ही झूकने वाला हूं। सरकार ने मुझे बदनाम करने में पूरी ताकत लगा दी।

अशोक गहलोत से ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

- **गहलोत ने लिखा, एआईसीसी महासचिव सचिन पायलट ने घर आकर पूर्व केन्द्रीय मंत्री राजेश पायलट की 25वीं पुण्यतिथि के कार्यक्रम का निमंत्रण दिया।**

रहे। उनके आकस्मिक निधन का दुख हमें आज भी बना हुआ है। उनके जाने से पार्टी को भी गहरा आघात लगा था।"

अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने इस मुलाकात के दौरान काफी देर तक चर्चा की। दरअसल, दोनों नेताओं के बीच लंबे समय से कटुता रही है। सन् 2020 के सियासी संकट के बाद कटुता काफी बढ़ गई थी। इसके बाद दोनों के बीच लगातार आरोप-प्रत्यारोप का दौर चला था। बाद में 25 सितंबर 2022 की घटना ने दोनों के रिश्तों को और बिगाड़ दिया था और बीच-बीच में दोनों नेता एक-दूसरे पर निशाना साधते रहे ।

आज की मुलाकात के बाद अब सबकी निगाहें राजेश पायलट की 25वीं पुण्यतिथि पर होने जा रहे कार्यक्रम पर है। इस कार्यक्रम में जुटने वाले नेताओं से भी सियासी कथानक बनेगा। अगर गहलोत इस कार्यक्रम में जाते हैं तो उनके समर्थक नेता भी बड़ी संख्या में जुटेंगे।

सचिन पायलट जब प्रदेशाध्यक्ष बनकर आए थे, तब उन्होंने बड़े नेताओं के घर जाकर मुलाकातों और सियासी मंत्रणाओं का दौर शुरू किया था। पायलट ने उस वक्त नेताओं को डिनर पर बुलाने और अलग -अलग नेताओं के यहां डिनर पर बैठकें करने का दौर शुरू किया था। इस डिनर डिप्लोमैसी की उस वक्त खूब चर्चा होती थी। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को एक जाजम पर लाने में डिनर डिप्लोमैसी को कारगर माना गया था।

फड़नवीस ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

नहीं हुई है। भाजपा ने नेतृत्व परिवर्तन को लेकर कोई औपचारिक जानकारी या बयान जारी नहीं किया है।

वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सक्रिय हैं। उन्होंने इस महीने के अंत में कैनडा में होने वाले जी 7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है, बावजूद इसके कि भारत और कैनडा के बीच राजनयिक संबंधों में तनातनी बनी हुई है। देश के अंदर भी वे कई महत्वपूर्ण पहलों में जुटे हुए हैं, जिनमें जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करना भी शामिल है।

सारांश यह है कि, सितंबर 2025 में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर अटकलें ज़रूर हैं, लेकिन सरकार या भाजपा की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, और यदि भविष्य में कोई उत्तराधिकारी तय किया जाता है तो उसकी घोषणा उचित आधिकारिक माध्यमों से ही की जाएगी।

रेल मंत्रालय ने ट्रेन चालकों के विश्राम नियमों में बदलाव किया

- **ट्रेन ड्राइवर्स की यूनियन, ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन ने बदलाव का विरोध किया।**

नई दिल्ली, 07 जून। रेल मंत्रालय ने ट्रेन के चालक दल के सदस्यों के लिए आउटस्टेशन विश्राम नियमों में बदलाव की घोषणा की है। इसका उद्देश्य विभिन्न रेलवे जोन और डिवीजनों में प्रचलित अलग-अलग प्रथाओं में एकरूपता लाना है। हालांकि, ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन (एआईएलआरएसए) ने इस कदम का कड़ा विरोध किया है और रेलवे बोर्ड को लिखे पत्र में इसे गैरकानूनी आदेश करार दिया है। यूनियन का दावा है कि यह नियम मंत्रालय के पूर्व आदेशों का उल्लंघन करता है।

रेल मंत्रालय के 3 जून को जारी एक सर्कुलर में सेंटर फॉर रेलवे इन्फॉर्मेशन सिस्टम (सीआरआईएस) के महाप्रबंधकों को संबोधित करते हुए कहा गया कि भारतीय रेलवे में रनिंग स्टाफ के लिए छह प्रकार के आउटस्टेशन रेस्ट नियम हैं। मामले की जांच के बाद, मौजूदा नियमों में बदलाव किए गए हैं। इसके तहत तीन प्रकार के रेस्ट नियम निर्धारित किए गए हैं।

आठ घंटे की ड्यूटी करने वालों को आठ घंटे का रेस्ट, पांच से आठ घंटे की ड्यूटी करने वालों को छह घंटे का रेस्ट, और पांच घंटे या उससे कम ड्यूटी करने वालों को ड्यूटी की अवधि से एक घंटे अधिक रेस्ट दिया जाएगा। मंत्रालय ने सीआरआईएस को निर्देश दिया कि क्रू मैनेजमेंट सिस्टम (सीएमएस) में अन्य सभी प्रकार के रेस्ट को अयोग्य माना जाए।

'महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव "फिक्स" थे, बड़े...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

- **राहुल ने कहा, महाराष्ट्र में एक लाख बूथ हैं, पर, 85 सीटों के 12 हजार बूथों में अधिकांशतः नए मतदाता जोड़े गए। यहाँ शाम 5 बजे बाद 600 वोट पड़े, जो हैरानी की बात है।**
- **राहुल ने कहा, विधानसभा चुनाव के बाद, जब हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को वीडियोग्राफी व सीसीटीवी फुटेज देने को कहा तो केन्द्र की भाजपा सरकार ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर नियमों में संशोधन कर दिया और सीसीटीवी फुटेज और वीडियो तक पहुंच सीमित कर दी।**

इतनी अविश्वसनीय थी कि पंजीकृत मतदाताओं की संख्या (9.70 करोड़) खुद सरकार के आंकड़ों से भी अधिक थी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, महाराष्ट्र के वयस्कों की कुल संख्या 9.54 करोड़ ही थी।"

राहुल गांधी ने फर्जी मतदाताओं को भाजपा की चुनावी "मैच-फिक्सिंग" की एक और रणनीति बताया।

कांग्रेस नेता ने ईसी की ओर से अंतिम मतदान प्रतिशत की रिपोर्टिंग में विसंगतियों का भी हवाला दिया और आरोप लगाया कि लक्षित बोनस वोटिंग ने भाजपा को ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर सर डॉन ब्रैडमैन बना दिया, जो अपनी 99.9 की औसत और 80 की स्ट्राइक रेट के लिए जाने जाते हैं।

उन्होंने कहाः "महाराष्ट्र में लगभग 1 लाख बूथ हैं, लेकिन अधिकांश नए मतदाता केवल लगभग 12,000 बूथों में जोड़े गए, जो उन 85 विधानसभा क्षेत्रों में हैं, जहां भाजपा को पिछले लोकसभा चुनावों में खराब प्रदर्शन का सामना करना पड़ा था।

औसतन हर बूथ में शाम 5 बजे के बाद 600 से अधिक वोट डाले गए। अगर हर वोट को डालने में 1 मिनट भी लगता, तो वोटिंग को 10 घंटे और चलना पड़ता। लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं, तो सवाल उठता है कि अतिरिक्त वोट कैसे डाले गए? और इसमें आश्चर्य नहीं कि एनडीए ने इन 85 में से अधिकांश सीटें जीत लीं।"

राहुल गांधी ने भाजपा के 89 प्रतिशत स्ट्राइक रेट को भी संदिग्ध बताया, जो अब तक का सबसे अधिक है और कहा, भाजपा को आज तक कभी ऐसा स्ट्राइक रेट नहीं रहा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए फोटो समेत मतदाता सूची साझा करने से इनकार कर दिया, जो एक और कड़ी थी चुनाव में, भाजपा की पकड़ मजबूत करने की।

उन्होंने लिखाः "इससे भी बुरा यह कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के एक महीने बाद ही, जब एक उच्च न्यायालय ने मतदान के सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी साझा करने का आदेश दिया, तब केन्द्र सरकार ने चुनाव आयोग से परामर्श कर 1961 के चुनाव आचरण नियम के सेक्शन 93(2)(ए) में संशोधन कर दिया, ताकि सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तक पहुंच सीमित की जा सके।"

राहुल आगे लिखते हैं कि "संशोधन और उसकी टाइमिंग, दोनों ही यह बताने के लिए काफी हैं कि कुछ छुपाया जा रहा है। एक जैसे या डुप्लीकेट ईपीआईसी नंबरों के खुलासे ने फर्ज़ी मतदान पर चिंता बढ़ा दी है, पर यह तो सिर्फ शुरुआत है।

राहुल गांधी ने लिखाः "मतदाता सूची और सीसीटीवी फुटेज सिर्फ दिखावा नहीं है, बल्कि जब लोकतंत्र का उल्लंघन हो रहा है, तब इनका इस्तेमाल लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए करना चाहिए। भारत की जनता का अधिकार है कि उसे भरोसा दिलाया जाए कि कोई रिकॉर्ड नष्ट नहीं किया गया है और न किया जाएगा।

अंत में राहुल गांधी ने लिखाः "यह अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है कि नवंबर 2024 में महाराष्ट्र में धांधली इस स्तर पर क्यों हुई। लेकिन चुनावी धांधली ठीक मैच-फिक्सिंग की तरह है, फिक्सिंग करने वाला पक्ष भले ही एक खेल जीत जाए, पर इससे संस्थाओं और परिणामों में लोगों के विश्वास को अपूरणीय क्षति होती है।" "मैच-फिक्स्ड चुनाव, लोकतंत्र के लिए ज़हर हैं।"

करोना के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

53 मौतें पिछले 16 दिन में हुई हैं। दिल्ली में 5 जून को पांच महीने के एक बच्चे की करोना से मौत हो गई। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 18 मरीजों ने जान गंवाई है।

इस तरह जनवरी से 6 जून तक देश में करोना के कुल 11,298 मामले आए हैं। इनमें से 48.54 प्रतिशत मरीज रिकवर हो चुके हैं, बाकी का इलाज जारी है। सिर्फ 0.52 प्रतिशत मामलों में मरीज की मौत हुई।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादकः- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालयः-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोनः2386031, 2386032, फैक्सः0744-2386033 बीकानेर कार्यालयः-कुम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोनः2200660, फैक्सः 0151-2527371 उदयपुर कार्यालयः-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोनः 2413092, 2418945, फैक्सः 0294-2410146 अजमेर कार्यालयः-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोनः 2627612, फैक्सः0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोनः 226422, 226423, फैक्सः 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोनः 230200, 230400, फैक्सः 07469-230600 चूरू कार्यालयः एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोनः 256906, 256907, फैक्सः01562-256908